Imbalance in provision of loans and Farm Sector

2567. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the farm sector is receiving less bank loans as compared to large and big industries;

(b) if so, whether Government are ready to do away with this imbalance;

(c) whether Government have received the views/reports of some State Goverments in this regard; and

(d) the steps taken by the Central Government to increase loan facilities among farmers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) According to the Report on Currency and Finance 1993-94 prepared by Reserve Bank of India data regarding gross bank credit to agriculture sector as well as medium and large industries is as under:

(Rs. in crores)

Year	Landing to agriculture sector	Landing to medium and large industries
March 1992	18157	47090
March 1993	19963	58636
March 1994	21208	57872

It may be seen from the above data that there has been continuous increase in the gross bank credit to agriculture sector. Credit is made available to all sectors of economy as per the requirement of individual activities which are otherwise found to be financially and technically viable.

(c) No, Sir.

(d) Simplification of loaning procedure introduction of pass-book system to the loanee farmers, disposal of application for loan in a time bound frame, non-insistence of security for short-term and long-term loans upto Rs. 15000/where movable assets are created, are some of the various steps taken to increase the loaning facility to the farmers.

Implementation of Integrated Pest Management Scheme

2568. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether his Ministry has decided to identify 50 districts all over the country for implementing integrated pest management scheme;

(b) if so, the criteria adopted in selecting the districts;

(c) the States in which these districts have been selected;

(d) the number of districts in the state of Madhya Pradesh which have been selected;

(e) whether it is a fact that Government have also decided to award a cash prize to the best village which had been adopting organic farming and minimum use of pesticides in the country; and

(f) the other incentives proposed to be provided under the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) and (b) Sir, during 1995-96 a total of 441 districts have been selected on the basis of pesticides consumption for implementing integrated pest management scheme.

(c) The Programme is under implementation in practically all the States.

(d) In Madhya Pradesh, a total of 28 districts have been selected.

(e) and (f) For promoting organic farming, there is a provision to award cash prizes to the best panchayat and farmers at the National and State levels under the Centrally Sponsored Scheme titled "Balanced and Integrated Use of Fertilizers".

IPM kits, publicity material (farmers field guide, poster etc.), and non-chemical inputs like pheromones biocides and biological control agents are provided free of cost to the farmers under IPM scheme.

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का कार्यकरण

2569. श्री राम जेठमलानी
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वर्ष 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह संसाधन जल संसाधनों के संबंध में निर्णय करने के लिए शीर्षस्थ निकाय है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संस्थान के क्या-क्या कार्य हैं;

(ङ) क्या गत दशक में इस निकाय की बहुत ही कम बैठक हो सकी है; और

(च) यदि हां, तो इस संस्थान की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और इनमें क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगया नायडू): (क) और (ख) जी हां। सरकार द्वारा मार्च, 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्री, राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक/उप राज्यपाल इसके सदस्य हैं। जल संसाधन मंत्रालय के सचिव इस परिषद के सचिव हैं। परिषद के कार्य इस प्रकार हैं:

I) राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित करना तथा समय-समय पर इसकी पुनरीक्षा करना।

II) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नदी घाटी आयोगों आदि द्वारा उसे प्रस्तुत की गई जल विकास योजनाओं (वैकल्पिक योजनाओं सहित) पर विचार करना तथा उनकी पुनरीक्षा करना।

III) ऐसे संशोधनों, जो उपयुक्त और आवश्यक समझे जाएं, के साथ जल योजनाओं की स्वीकृति की सिफारिश करना।

IV) योजनाओं अथवा उसके घटकों पर पूर्ण विचार करने के लिए ऐसे और अध्ययन, जो आवश्यक हो, करने के निदेश देना।

V) जल योजनाओं के विशिष्ट तत्वों के संबंध में अंतर्राज्यीय मतभेदों और ऐसे अन्य मुद्दे, जो परियोजनाओं की आयोजना अथवा कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं, को हल करने के तौर-तरीकों पर सलाह देना।

VI) इष्टतम विकास और लोगों के अधिकतम लाभों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभिन्न लाभग्राहियों द्वारा जल संसाधनों के उचित वितरण एवं उपयोग की पद्धतियां व प्रक्रियाएं, प्रशासनिक प्रबंध व विनियमनों पर सलाह देना।

VII) ऐसी अन्य सिफारिशें करना जो विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधनों के तीव्र, पर्यावरणीय दृष्टि से सही व किफायती विकास को बढ़ाएगी।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) परिषद की अब तक दो बैठकें हुई हैं। पहली बैठक 30.10.85 को हुई थी जिसमें राष्ट्रीय जल नीति के विषय से संबंधित एक निबंध पर विचार किया गया था और राष्ट्रीय जल नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए "केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य के मुख्य मंत्रियों के एक दल" का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री हैं। मंत्रियों के दल द्वारा राष्ट्रीय जल नीति के मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, परिषद ने अपनी दूसरी बैठक 9.9.1987 को की और राष्ट्रीय जल नीति को सर्वसम्मति से पारित किया।

Survey on Iron-Ore deposit in Uttar Pradesh and Bihar

2570. SHRI DIGVIJAY SINGH:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether the Geological Survey of India (GSI) has conducted any survey to assess the availability of iron-ore deposits in Uttar Pradesh and Bihar during the last two years;

(b) if so, the findings thereof; and

(c) the steps being taken to extract iron-ore from the selected sites, site-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

Expansion of area under rice cultivation in Andhra Pradesh

2571. SHRI YERRA NARAYAN SWAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have any plans to expand the area under rice cultivation in Andhra Pradesh;